पटना उच्च न्यायालय में

1934 की सिविल संदर्भ सं. 5

निर्णय लिया/ दिया गयाः 05.02.1935

याचिकाकर्तागणः **प्रांतसंदर्भ में आर. एस. प्लीडर, समस्तीपुर**

बनाम

लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879-धारा 14-अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर जलत बयान देने के विरुद्ध आरोप- विरोधाभासी बयान-अधिवक्ता द्वारा क्लर्क के उकसावे पर दिए गए बयान-अधिवक्ता की पहचान-अधिवक्ता द्वारा याचिका की संतुष्टि हेतु आवश्यक पहचान (कंडिका-1,6 और 7)

शुरू में अधिवक्ता द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों का अदालत को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था-अदालत के समक्ष दिए गए पल के बयानों के दबाव में-दिए गए पल के बयान के भ्रम में जो जानबूझकर असत्य है-बयान अदालत में जानबूझकर की गई धोखाधड़ी का गठन नहीं करता है-छह महीने के लिए निलंबित अधिवक्ता/याचिकाकर्ता। (कंडिका-9,10)

मोहम्मद नूर, न्यायधीश

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिवक्ता/याचिकाकर्ता फर्जी मुकदमों की स्थापना में किसी भी साजिश के लिए दोषी नहीं होने और संतोष का फर्जी आवेदन दायर करने के लिए-क्लर्क ने वकील की अनुभवहीनता का लाभ उठाया-कानूनी पेशे के सदस्यों द्वारा झूठी गवाही-एक गंभीर मामला-न्याय के प्रशासन को अवरुद्ध करने के लिए आम जनता के लिए बुरा उदाहरण स्थापित करता है-झूठी गवाही की गई लेकिन अदालत को धोखा देने का इरादा नहीं है-पारित सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। (कंडिका-11,12)

पटना उच्च न्यायालय में

1934 की सिविल संदर्भ सं. 5

निर्णय लिया/ दिया गयाः 05.02.1935

याचिकाकर्तागणः **प्रांतसंदर्भ में आर. एस. प्लीडर, समस्तीपुर**

बनाम

माननीय न्यायाधीशगण/गणपूर्तिः

वॉर्ट, मोहम्मद नूर और सी. एम. अग्रवाल, न्यायमूर्तिगण

अधिवक्ता

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः सैयद सुल्तान अहमद

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिए: जनक किशोर

निर्णय

वॉर्ट, न्यायमूर्ति

1. यह धारा 14, कानूनी व्यवसायी अधिनियम के तहत दरभंगा के जिला न्यायाधीश द्वारा समस्तीपुर के एक वकील के खिलाफ एक संदर्भ है। उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने यह जानते हुए कुछ बयान दिए कि वे झूठे हैं। वे बयान कुछ कार्यवाही के दौरान दिए गए थे जिन्हें मैं संदर्भित करने का प्रस्ताव करता हूं। मामला इस तरह से उठा। 20 जनवरी 1931 को समस्तीपुर अनुमंडल में 3 बीघा भूमि के जमींदार के रूप में एक भागवत प्रसाद मिसर और अन्य व्यक्तियों की ओर से दो किराए के मुकदमे दायर किए गए थे। बस एक महीने बाद भागवत प्रसाद मिसर और अन्य वादियों की ओर से संतोष की दो याचिकाएं भी दायर

की गईं। इस मामले के बारे में शायद और कुछ नहीं सुना गया होता अगर यह तथ्य नहीं होता कि भागवत प्रसाद ने उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया होता, जो उन किराए के मुकदमों में प्रतिवादी के रूप में पेश हुआ था, कुछ आपराधिक कार्यवाही में बाबाजी पर आरोप लगाते हुए। ठाकुर (प्रतिवादी) ने विवादित भूमि पर कुछ धान लूटा था। बाबाजी ठाकुर को 4 अगस्त 1932 को बरी कर दिया गया था, उन्होंने इन किराए के मुकदमों में कागजात पेश किए थे, जिनके लिए मैंने संदर्भ दिया था और जिन पर आपराधिक अदालत ने भरोसा किया था। इसके बाद भागवत प्रसाद मिसर ने मुनासीफ को एक बाबाजी ठाकुर और नागेंद्र प्रसाद पर मुकदमा चलाने के लिए आवेदन किया, जो हमारे सामने वकील के क्लर्क हैं, इन दो किराए के मुकदमों को धोखाधड़ी से दायर करने के लिए। मुन्सिफ के समक्ष एक जांच की गई थी और इस जांच के दौरान ही शिकायत किए गए बयान आर द्वारा दिए गए थे और जो कहा जाता है कि उनकी जानकारी में गलत थे। उसने इस बयान की शिकायत की थीः

> मैं यह नहीं बता सकता कि क्या भागवत प्रसाद मिसर, जिनसे मैं उस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मिला था, जो किराए के मुकदमे का जिक्र कर रहा था) वही भागवत प्रसाद मिसर थे जिनसे मैं इस विविध मामले के लंबित रहने के दौरान मिला था (यह मामला मुन्सिफ के समक्ष है कि क्या कथित प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए)।

2. और फिर अपीलार्थी भागवत प्रसाद की ओर सही इशारा करते हुए गवाह ने कहाः

> जब मैंने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि जिस व्यक्ति से मैं इस मामले के लंबित रहने के दौरान मिला था, क्या वह वही भागवत प्रसाद मिसर था जिसने मुझे किराए के सूट में वकालतनामा भेंट किया था, तो मैं वास्तव में उलझन में था।

3. उस जाँच के बाद जिसमें मुन्सिफ़ ने संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, जिला न्यायाधीश को एक अपील की गई थी जिसके परिणामस्वरूप सबूत फिर से

लिए जाने पर मुन्सिफ़ को रिमांड पर ले लिया गया और उस अवसर पर बी. एस. ने यह बयान दियाः

> मैंने कहा कि मैं 1931 के किराया मुकदमे संख्या 18 और 19 के तीन वादियों को जानता हूं।

4. फिर अदालत द्वारा पूछे जाने पर, वह कहता हैः

> प्रश्न वर्तमान काल में होने के कारण मैंने वर्तमान काल में उत्तर दिया, क्योंकि विविध मामले के बाद से मुझे वादी को नहीं जानना कहा जा सकता है, क्योंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस विविध मामले के लंबित होने के दौरान जानता था। मैंने श्यामा बाबू (जो वादी के वकील थे) से कहा कि मैं 1931 के किराया मुकदमे संख्या 18 और 19 के वादी को नहीं जानता था, क्योंकि उस समय मैं वादी को उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए नहीं मिला था।

5. फिर उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट विरोधाभासों के बारे में स्पष्टीकरण देने का इरादा किया, और फिर अपने स्पष्टीकरण के अंत में और अदालत को जवाब देते हुए यह बयान दियाः

> वर्तमान कथन कि मैंने वर्तमान विविध मामले की स्थापना से पहले भागवत प्रसाद मिसर को मान्यता नहीं दी थी, सही है, और मेरा पिछला कथन कि इस भागवत प्रसाद मिसर ने, जो विविध मामले में अपीलकर्ता हैं, वास्तव में उन किराए के मुकदमों में मुझे वकालतनामा प्रस्तुत किया था, गलत है।

6. यह बयान उस बयान का विरोधाभास है जो उन्होंने मुन्सिफ के समक्ष पहली जांच में दिया था जिसमें उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि उन्होंने किराए के मुकदमे में कथित वादी भागवत प्रसाद मिसर की पहचान की थी। मैंने इन बयानों को कुछ विस्तार से उन कारणों के

लिए संदर्भित किया है जो वर्तमान में दिखाई देंगे। मामला अंततः जिला न्यायाधीश के समक्ष दूसरी बार मुन्सिफ के आदेश की जांच करने के बाद आया जिसमें मुन्सिफ ने संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था और जहां तक आदेश के उस हिस्से का संबंध था, जिला न्यायाधीश ने इसे दरकिनार कर दिया, लेकिन उनके आदेश का परिणाम संदर्भ था जो अब इस न्यायालय के समक्ष आता है। अब आर की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि 7 मई 1932 को मुन्सिफ द्वारा पहली जांच की तारीख को दिया गया बयान गलत था। ऐसा होने पर, एकमात्र सवाल और कानूनी पेशे के किसी सदस्य द्वारा इस तरह के बयान की प्रकृति के बारे में कोई सवाल नहीं है, जो कि वास्तविक रूप से झूठी गवाही है और निश्चित रूप से घोर पेशेवर कदाचार है, उन परिस्थितियों में न्यायालय का आदेश क्या होना चाहिए। आर की ओर से श्री जनक किशोर तर्क देते हैं कि जिन साक्ष्य का मैंने संदर्भ दिया है, वे आरोपी द्वारा जानबूझकर गलत बयान देने या अदालत को गुमराह करने के प्रयास का खुलासा नहीं करते हैं, बल्कि उस समय के दबाव में दिए गए मूर्खतापूर्ण बयान से अधिक कुछ नहीं है और सबसे बुरी बात यह है कि वह खुद को उस कठिन स्थिति से बाहर निकालने के लिए एक झूठे बयान की प्रकृति के प्रयास से अधिक कुछ नहीं है जिसमें उन्होंने खुद को पाया था।

7. शुरू में यह माना जा सकता है कि आर का कथित वादियों के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करने के अलावा इन झूठे किराए के मुकदमों की स्थापना से कुछ लेना-देना था; लेकिन न तो जिला न्यायाधीश और न ही जांच करने वाले मुन्सिफ की राय है कि आर साजिश में है और वास्तव में, मुझे लगता है, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि उस तथ्य का कोई सबूत नहीं है। हमारे सामने मौजूद तथ्यों से जो बात पर्याप्त रूप से प्रकट होती है, वह यह है कि क्लर्क के उकसावे पर ही उस कार्रवाई में वादी की पहचान की गई थी। 21 फरवरी 1931 को संतुष्टि याचिका के मामले में पहचान आवश्यक थी। यह देखा जाना बाकी है कि विद्वान अधिवक्ता का तर्क हमारे सामने साक्ष्य पर उचित है या नहीं। जब हम मई

1932 में मुन्सिफ के समक्ष वादी द्वारा दिए गए बयान का विश्लेषण करने आते हैं, तो हम पहली बार में देखते हैं कि उनका बयान थाः

> मैं यह नहीं बता सकता कि भागवत प्रसाद मिसर, जिनसे मैं उस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मिला था, वही भागवत प्रसाद मिसर थे या नहीं, जिनसे मैं उस विविध मामले के लंबित रहने के दौरान मिला था।

8. अगर उनका बयान वहीं रुक जाता तो इस मामले के बारे में थोड़ा और सुना जाता; लेकिन फिर वे भागवत प्रसाद मिसर की ओर इशारा करते हुए कहते हैंः

> वह वह व्यक्ति है जिसने मुझे उपरोक्त किराए के सूट में वकालतनामा भेंट किया था।

9. फिर अदालत को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पिछला बयान दिया था, अर्थात जिस बयान में उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि क्या वे वही भागवत प्रसाद मिसर थे जब उन्होंने अदालत को जवाब देते हुए यह बयान दिया था, तो वे कहते हैंः"मैं वास्तव में उलझन में था। "यह उत्तर मामले को कुछ गंभीर पहलू देता है; लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि पहली बार में वह संदेह व्यक्त करता है। फिर अदालत द्वारा दबाव डाले जाने पर वह दृढ़ता से कहता है कि उसने भागवत प्रसाद मिसर की पहचान की। लेकिन इस संबंध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जांच के बाद के चरण में, यानी जब मामला जिला न्यायाधीश द्वारा रिमांड पर मुन्सिफ के समक्ष आया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले अवसर पर भागवत प्रसाद मिसर की पहचान करने का बयान गलत था। हमने इस मामले पर बहुत सावधानी से विचार किया है और जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, वह यह है कि आर द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों के संबंध में कि पहली बार में उनका अदालत को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था, कि उनके पहले बयान को किसी भी अर्थ में गलत नहीं माना जा सकता है, कि उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि क्या भागवत प्रसाद मिसर

विविध मामले में भागवत प्रसाद मिसर के समान व्यक्ति थे और यह केवल उस अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए था, जिसका मैंने एक पल पहले उपयोग किया था, उस क्षण के दबाव में जब वह आगे बढ़े और अदालत को जवाब देते हुए जोर से कहा कि बातचीत में उन्होंने निश्चित रूप से भागवत प्रसाद मिसर की पहचान की। मैं फिर से दोहराता हूं कि बाद के अवसर पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले अवसर पर उनका बयान गलत था। इसके अलावा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री जनक किशोर ने वकील की ओर से जो तर्क दिया है वह सही है, कि इस क्षण के भ्रम में उन्होंने एक बयान दिया जो इसके चेहरे पर जानबूझकर असत्य प्रतीत होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह गलत था। लेकिन वह केवल कुछ वर्षों के लिए व्यवहार में अपेक्षाकृत एक युवा व्यक्ति है और जैसा कि मैंने कहा है, हम संतुष्ट हैं कि उन्होंने जो कहा वह अदालत में जानबूझकर की गई धोखाधड़ी नहीं है। इसके असत्य के तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वह कानूनी पेशे का सदस्य है और उसका कर्तव्य न केवल अपने मुवक्किलों के प्रति बल्कि उस न्यायालय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है जिसके समक्ष वे व्यवहार करते हैं।

10. इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लेकिन इस तथ्य की अवहेलना नहीं करते हुए कि यह एक बयान था जो स्वीकार्य रूप से गलत था, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पारित करने के लिए उचित आदेश यह है कि आर को आज से छह महीने के लिए निलंबित किया जाए।

मोहम्मद नूर, न्यायामूर्ति।

11. मैं सहमत हूँ। मुझे अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि संबंधित वकील फर्जी मुकदमों की स्थापना और संतुष्टि के फर्जी आवेदन को दायर करने में किसी भी साजिश का दोषी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि उनके किरानी ने उनकी अनुभवहीनता का लाभ उठाया और

उनके माध्यम से यह काम करने में कामयाब रहे कि यह वास्तविक भागवत प्रसाद मिसर की ओर से किया जा रहा था। सबसे अधिक संभावना है कि क्लर्क ने वास्तविक वादी को व्यक्त करने के लिए किसी को नियुक्त किया। यह कि साजिश में वकील का कोई हाथ नहीं था, इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि अदालत में उससे पूछताछ किए जाने से पहले वह चाहता था और उसने पूरी कहानी स्थानीय बार वकील समूदाय/विधिता वर्ग नेता बाबू श्यामा पद बनर्जी को बताई। उन्होंने निश्चित रूप से उनसे कहा कि वह स्वयं वादी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उन्हें अपने किरानी के आश्वासन पर काम करना होगा। बाद में ऐसा लगता है कि वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के अदालत द्वारा उसके सामने सबूत देने के लिए बुलाया गया था। वहाँ भी एक निश्चित स्तर तक वह सच बोल रहा था और मुझे लगता है कि यह सही था जब उसने कहा कि वह वास्तविक भागवत प्रसाद मिसर की पहचान नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने निश्चित रूप से कहा था कि वह यह कहने की स्थिति में नहीं था कि क्या वह व्यक्ति जिसकी ओर से उसने किराए के मुकदमे दायर किए और संतुष्टि याचिका दायर की, वह वह व्यक्ति था जो बाबाजी ठाकुर के अभियोजन के लिए विविध कार्यवाही कर रहा था।

12. तब कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण उन्होंने बयान बदल दिया, मुझे नहीं लगता कि अदालत के लिए उन्हें वास्तविक भागवत प्रसाद मिसर की पहचान करने के लिए कहना क्यों आवश्यक था, जबकि गवाह पहले ही कह चुका था कि वह अपनी पहचान के बारे में निश्चित नहीं था। जब उसे उस आदमी की पहचान करने के लिए कहा गया, तो शायद उसने सोचा कि वह किसी कठिनाई में पड़ गया है और जब तक वह यह नहीं कहता कि वह वही आदमी है, तब तक वह इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। कानूनी पेशे के सदस्यों द्वारा झूठी गवाही, इस सवाल के अलावा कि यह एक आपराधिक अपराध है, पेशे के दृष्टिकोण से एक बहुत ही गंभीर मामला है। इस तथ्य के अलावा कि यह पेशे को नुकसान पहुंचाता है, यह आम जनता के लिए एक बहुत ही खराब उदाहरण स्थापित करता है और न्याय के प्रशासन में एक बड़ी

बाधा है। इसलिए, यदि और जब कानूनी पेशे के सदस्यों द्वारा झूठी गवाही के मामलों का पता चलता है तो संबंधित सदस्य सबसे गंभीर सजा का हकदार है जो यह न्यायालय कानूनी पेशे पर अपने अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दे सकता है। लेकिन मुझे यकीन है कि यह उन मामलों में से एक नहीं है; जिसमें उस पाठ्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं कि झूठी गवाही उन परिस्थितियों में की गई थी जो दर्शाती हैं कि इसका उद्देश्य न्यायालय को धोखा देना या उस पर कोई धोखाधड़ी करना नहीं था। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि मामले की परिस्थितियों में जिस सजा को पारित करने का मेरे प्रभु/स्वामी ने आदेश दिया है, वह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

सी.एम. अग्रवाल, जे.

13. मैं प्रस्तावित आदेश से सहमत हूँ।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।